P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में सतत् विकास लक्ष्यों की सुशासन में भूमिका

जनक सिंह मीना
सहायक प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय, जोधपुर
राजस्थान, भारत

सारांश

आज वैश्विक स्तर पर सतत् विकास पर विचार–विमर्श के साथ प्रयास भी हो रहे हैं। दुनिया के देशों में विकास की बात होती है तो प्रमुख रूप से तीन प्रकार के विकास उभर कर सामने आते हैं, यथा (1)संतुलित विकास (2)समन्वित विकास, और (3)सतत् या टिकाऊ विकास। सतत् विकास की अवधारणा वर्तमान के साथ भविष्य को भी समेटने का प्रयास करती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक 15 वर्षीय कार्यक्रम सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों के अनुमोदन से स्वीकार किया गया जिसे 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी बनाते हुए वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की गई जिससे अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की संकल्पना करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्य शब्द : सुशासन, जवाबदेहता, गुणवत्ता, साझेदारी, टिकाउ।

प्रस्तावना

"एजेंडा 2030 के पीछे की हमारी सोच जितनी ऊँची है हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र हैं। इनमें उन समस्याओं की प्राथमिकता दी गई है, जो पिछले कई दषकों से अनसुलझी हैं और इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में हमारे विकसित होती समझ की झलक मिलती है। मानवता के $^1/_6$ हिस्से के सतत् विकास का विष्व और हमारे सुंदर पृथ्वी के लिए बहुत गहरा असर होगा।"

–नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार

सर्वप्रथम सुशासन की अवधारणा को जानने के लिए आवश्यक है कि शासन या अभिशासन क्या है? अभिशासन एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसके माध्यम से समाज में निहित तत्व शक्ति, प्राधिकार एवं प्रभाव का प्रयोग करते हैं और जनता से संबंधित नीतियों और निर्णयों को कार्यान्वित करते हैं। विश्व बैंक ने अभिशासन के तीन विशिष्ट पहलुओं की पहचान की है, वे हैं[1] (i) राजनीतिक शासन का स्वरूप; (ii) वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विकास हेतु किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों का प्रबंधन करते हुए प्राधिकार का प्रयोग किया जाता है; तथा (iii) नीतियों की रूपरेखा तय करने, उनके निर्धारण और कार्यान्वयन तथा प्रकार्यों के निर्वहन में सरकार की क्षमता। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन को सहस्राब्दिक विकास लक्ष्यों (MDGs) का एक अत्यावश्यक घटक माना है क्योंकि यह गरीबी, असमानता एवं मानवजाति की अन्य अनेक बुराइयों के विरूद्ध संघर्ष के लिए आधारभूमि की रचना करता है।[2] सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए शुचिता, दक्षता और प्रभावी शासन व्यवस्था आदि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। विश्व बैंक ने सुशासन की निम्न विशेषताएँ बताई हैं–

1. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव
2. सरकारी संस्थाओं की जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता
3. सत्ता का विकेन्द्रीकरण
4. प्रशासन में जनता की भागीदारी
5. सामाजिक–आर्थिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता
6. मितव्ययिता
7. कार्यकुशलता
8. प्रशासन में नैतिकता
9. वंचित वर्गों का संवर्द्धन
10. पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विकास पर बल।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र में सतत् विकास के लक्ष्यों में सुशासन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है। हम किसी भी देश के संदर्भ में बात करते हैं, तो अन्ततः सभी का उद्देश्य देश में बेहतर सुविधाएँ, सेवाएँ, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, पारदर्शी शासन एवं प्रशासन, बेहतर लोक वितरण प्रणाली, उच्च तकीनकी एवं उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ बेहतर मानवीय विकास की संभावनाओं को तलाशना रहता है। यहाँ हम भारत के संदर्भ में सुशासन के लक्ष्यों का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) मानव विकास प्रतिवेदन 1991 में सतत् विकास को परिभाषित किया गया है– "सतत् विकास ऐसा विकास है जो स्वास्थ्य, अभिरक्षा, शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण को श्रेयस्कर बनाता है।"[3] सतत् विकास वास्तव में कतिपय निश्चित लक्ष्यों का एक पुँज है जिसमें निम्न लक्ष्य निहित हैं–

1. सभी मानवों की मूलभूत आवश्कताएँ जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा आत्मसम्मान पर्याप्त रूप में सम्पुष्ट होने चाहिए।
2. विकास प्रक्रियाएं इतनी सुस्पष्ट होनी चाहिए कि आर्थिक संतुलन एवं पर्यावरणिक शुद्धता कम से कम विचलित हो, तथा
3. सर्वव्यापकता हेतु सभी देशों एवं जनता को हाथ मिलाने होंगे तथा एक–दूसरे को सहयोग देना होगा ताकि एक ऐसी दुनिया बनाई जा सके जिसमें पूर्वोक्त दोनों लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए सतत् विकास के 17 लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को 2030 के लिए वैश्विक एजेंडे का मूलमंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है–'कोई पीछे न छूटे।' इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यूहरचना की क्रियान्विति के लिए भी प्रासंगिक होना चाहिए। विकास को अपने सभी आयामों में सभी के लिए, हर जगह समावेशी होना चाहिए और उसका निर्माण हर किसी की विशेषकर सबसे कमजोर (गरीब) और हाशिए के लोगों की भागीदारी से होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने सतत् विकास के निम्नलिखित 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं[4]–

शून्य गरीबी (No Poverty)

गरीबी का हर रूप में हर जगह उन्मूलन।

शून्य भुखमरी (Zero Hunger): शून्य भुखमरी, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् खेती को प्रोत्साहन।

उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली (Good Health and Well Being)

उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और हर उम्र में सबकी खुशहाली को प्रोत्साहन।

गुणवत्तापूर्ण षिक्षा (Quality Eduction)

समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सबके लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहन।

लैंगिक समानता (Gender Equality)

लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना।

स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (Clean Water and Sanitation)

सबके लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना।

सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा (Affordable & Clean Energy)

सस्ती, विश्वसनीय, सतत् और आधुनिक ऊर्जा सुलभता सुनिश्चित करना।

उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि (Decent Work and Economic Growth)

निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक वृद्धि, सबके लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं उत्कृष्ट कार्य।

उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं (Industry, Innovation and Infrastructure)

जानदार बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को प्रोत्साहन तथा नवाचार को संरक्षण।

असमानताओं में कमी (Reduced Inequalities)

देशों के भीतर और उनके बीच असमानताएं कम करना।

संवहनीय शहर और समुदाय (Sustainable Cities and Communities)

शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित, बेहतर और संवहनीय बनाना।

संवहनीय उपभोग और उत्पादन (Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns)

उपभोग और उत्पादन के संवहनीय स्वरूप को सुनिश्चित करना।

जलवायु कार्यवाही (Climate Action)

जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का सामना करने के लिए तत्काल कार्यवाही करना।

जलीय जीवों की सुरक्षा (Life Below Water)

जलीय जीवों की सुरक्षा सतत् विकास के लिए महासागरों, सागरों और समुंद्री संसाधनों का संरक्षण और संवहनीय उपयोग।

थलीय जीवों की सुरक्षा (Life on Land)

थलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों का संवहनीय प्रबंधन, मरूस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना तथा ठीक करना तथा जैव विविधता क्षति को रोकना।

शांति, न्याय और सषक्त संस्थाएं (Peace, Justice and Strong Institutions)

सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाजों को प्रोत्साहन सबके लिए न्याय सुलभ कराना और सभी स्तरों पर असरदार, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं की रचना करना।

लक्ष्य हेतु साझेदारी (Partnerships for Goals)

क्रियान्वयन के साधनों को सशक्त करना और सतत् विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को नई शक्ति देना।

4 अगस्त, 2015 को संयुक्त राष्ट्र में महत्त्वकांक्षी 'सतत् विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals) प्रस्तुत किया गया जिसमें 'सतत् विकास एवं रोजगार' पर विशेष बल दिया गया है। सतत् विकास लक्ष्य (जो वर्ष 2016–2030 तक के लिए लक्षित हैं), ने पहले से ही क्रियान्वित 'सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (Millenium Development Goals 2000-2015) का स्थान ले लिया। सतत् विकास लक्ष्य में ऊपर वर्णित 17 मुख्य विकास लक्ष्यों तथा सहायक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए 5P (People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership) पर विशेष बल दिया गया है।

'ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्डः द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के संकल्प को, जिसे सतत् विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं यथा (i) सामाजिक समावेश, (ii) आर्थिक विकास और (iii) पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। भारत के विकास संबंधी अनेक लक्ष्यों को सतत् विकास में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे अपने कार्यक्रम सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं जिनमें प्रमुख हैं– मेक इन इण्डिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्किल इंडिया आदि। भारत सरकार 'सबका साथ–सबका विकास' के नारे के साथ सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत हैं।

4T

Technical Upgradation तकनीकी उन्नयन
Techniques of Management प्रबन्धन तकनीक
Training प्रशिक्षण
Transparency पारदर्शिता

भारत में संयुक्त राष्ट्र दशा निर्धारित किए गए सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सुशासन हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं, जिनमें प्रमुख हैंः–

भ्रष्टाचार मुक्त भारत

भारत में शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व निर्धारण एवं जवाबदेहता सुनिश्चित करने के लिए नवीन समयबद्ध सेवाएं, तकनीकों, प्रक्रियात्मक सरलीकरण, त्वरित प्रतिक्रिया, कम्प्यूटरीकरण एवं एकल खिड़की जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा कर लालफीताशाही, अनावश्यक देरी, लेन–देन, जैसी बुराईयों पर काबू पाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

नीति आयोग का गठन

भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके संरचनात्मक एवं कार्यात्मक बदलाव करने हुए नीति आयोग ;छंजपवदंस प्देजपजनजपवद वित ज्तंदेवितउपदह प्दकपंद्ध का गठन किया गया है। नीति आयोग एक

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सुशासन के मापदण्ड निम्न माने जाते हैंः–

1. सरकार औा बाजार के मध्य संबंध
2. सरकार और नागरिकों के बीच संबंध
3. सरकार और निजी क्षेत्रों के मध्य संबंध तथा
4. चुने हुए अधिकारियों एवं नियुक्त अधिकारियों के बीच संबंध।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ष 1906 में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कहा था कि इस हेतु–

1. कानून का शासन
2. कार्यकुशलता में वृद्धि
3. जवाबदेही
4. भ्रष्ट्रचार मुक्त प्रशासन तथा
5. वित्तीय कुशल प्रबन्ध आदि का होना आवश्यक है।

वहीं सयुक्त राष्ट्र में मानव विकास तथा राजनीतिक संस्थाओं में सुधार के साथ–साथ सुशासन के लिए आठ विशेषताओं का उल्लेख किया हैं, वे हैं–

1. सहभागिता (Participation)
2. विधि का शासन (Rule of law)
3. पारदर्शिता (Transparency)
4. उत्तरदायित्व (Responsiveness)
5. बहुतम / मतैक्य (Consensus oriented)
6. जवाबदेहता (Accountability)
7. समानता एवं समावेशन (Equitable and inclusiveness)
8. प्रभावशीलता एवं दक्षता (Effectiveness and efficiency)

प्रो. ओ.पी. मिनोचा ने अपने लेख गुड गवर्नेंस एण्ड न्यू मैंनेजमेंट परस्पेक्टिव में सुशासन को निम्नानुसार दर्शाया गया है–

4D

Decentralization विकेन्द्रीकरण
Delegation प्रत्यायोजन
Democratization लोकतंत्रीकरण
Debeauracratization विनौकरशाहीकरण

नीतिगत प्रबुद्ध मण्डल ;जैपदा जंदाद्ध है जो वर्तमान में वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ राष्ट्रीय जरूरतों पर केन्द्रित है।

अवसंरचना का विकास

देश में संरचनात्मक बदलाव इस बात को ध्यान में रखकर किये जा रहे हैं जिससे देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन के साथ संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास के लक्ष्य भी प्राप्त किये जा सकें।

स्वच्छ भारत अभियान

देश में हर स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छ वातावरण बनाने के प्रयास हो रहे हैं। पूरे देश में शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है जिससे खुले में शौच से उत्पन्न बीमारियों एवं समस्याओं से निजात पाया जा सके।

स्किल इंडिया और मेक इन इण्डिया कार्यक्रम

देश में नौजवानों में काम करने की क्षमता बढ़ाने और रोजगार मुहैया करवाने के लिए स्किल इण्डिया और मेक इन इण्डिया कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप में सक्षम बनाने तथा सशक्त सूचना समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है।

बेची बचाओ – बेटी पढ़ाओ योजना

भारत में लैंगिक समानता लाने एवं लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इनके अलावा अन्य अनेक कार्यक्रम एवं योजनाऐं देश में क्रियान्वित की जा रही हैं जो प्रशासन के माध्यम से सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक साबित हो रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं – सहकारी संघवाद की क्रियान्विति, ऊर्जा क्षेत्रों का विकास, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं मरम्मत, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना, पहले पड़ौसी की नीति, आपदा प्रबन्धन एवं मानवीय दृष्टिकोण, मन की बात कार्यक्रम, सबका साथ–सबका विकास की विचारधारा, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, नागरिक पहले का सिद्धान्त, ;ब्पजप्रमद थ्तपमदकसल ळवअमतदउमदजद्ध सांसद आदर्श ग्राम योजना इत्यादि।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 28 सितम्बर 2018 को भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने नई दिल्ली में सतत् विकास फ्रेमवर्क 2018–2022 पर हस्ताक्षर किए। इसमें एक नया भारत बनाने को गति प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है जिससे भारत गरीबी मुक्त हो सके। विजन दस्तावेज में एक ओर 2030 तक पूरे देश में सौ प्रतिशत साक्षरता एवं विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने, सड़क व रेल मार्ग, शुद्ध हवा, पानी की सुनिश्चितता, पर्यावरण आदि को सम्मिलित किया गया है। सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, 2018 में वर्ष 2030 सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति को दर्शाया गया है जिसमें सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2018 सम्यक 62 प्राथमिक संकेतकों पर आधारित है जिनका चयन नीति आयोग द्वारा किया गया है। इसमें सतत् विकास के 17 लक्ष्यों में से 103 के आंकड़ों को सम्मिलित किया गया है तथा सतत् विकास लक्ष्यों में 13 के आंकड़ां को सम्मिलित किया गया है तथा सतत् विकास लक्ष्य 12, 13 एवं 14 का मापन संभव नहीं हो सका है और लक्ष्य 17 को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है।

2015 में स्वीकार किये गए संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत आधी यात्रा पूरी कर ली है। भारत के बौद्धिक मण्डल नीति आयोग एवं संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की स्थिति निम्नानुसार है–

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	स्कोर (अधिकतम 100)
1.	हिमाचल प्रदेश	69
2.	केरल	69
3.	चण्डीगढ़	68
4.	तमिलनाडु	66
5.	पुदुचेरी	65
6.	आन्ध्र प्रदेश	64
7.	गोवा	64
8.	गुजरात	64
9.	कर्नाटक	64
10.	महाराष्ट्र	64

स्रोत– नीति आयोग

भारत में 29 राज्यों में से उत्तर प्रदेश–42, बिहार–48, असम–49 के साथ नीचे के पायदान पर है, झारखण्ड–50, उड़ीसा, नागालैण्ड व अरूणाचल प्रदेश–51, मेघालय, मध्यप्रदेश–52, जम्मू एवं कश्मीर–53, मिजोरम, मणिपुर–59, उत्तराखण्ड, पंजाब – 60, तेलगांना–61, आन्ध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक व महाराष्ट्र–64, तमिलनाडु–66, हिमाचल प्रदेश व केरल–69, स्कोर के साथ प्रथम स्थान है। केन्द्र शासित प्रदेशों में चण्डीगढ़–68, पदुचेरी–65, दमन व द्वीप–63, दिल्ली–62, लक्ष्यद्वीप–62, अण्डमान व निकोबार दीप समूह–58 एवं दादरा व नगर हवेली–57 स्कोर के साथ अन्तिम स्थान पर है।

(नोटः– सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में 0–49 आकांक्षी, अच्छा प्रदर्शन – 50 – 64, अग्रणी 65–99, लक्ष्य प्राप्तकर्ता : 100)

संदर्भ ग्रंथ सुची

1. *World Bank, Governance : The World Bank's Experience, World Bank Publication, Wasgington D.C., (1994)*
2. *World Bank Global Monitoring Report, Millennium Development Goals: Strengthening Mutual Accountability, Aid, Trade and Governance (2006)*
3. *प्रो. प्रीता जोशी, विकास प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर्स, जयपुर, 2011, पृ.177*
4. *https://in.org.one.un.org Dated 8 september 2019*
5. *IIPA Souvenir 2019*
6. *नीति आयोग, प्रगति प्रतिवेदन 2018*